

“ मुख्य समाचार ”

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा—एड्स से पीड़ित रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत्त।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता व प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दिया बल।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से पुलिस कर्मियों की परिवहन निगम की बसों में यात्रा सुविधा फिर से बहाल करने की उठाई मांग।
- प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से जनजीवन प्रभावित— 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग व 3 सौ 38 सड़कें अवरुद्ध।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एड्स से पीड़ित रोगियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत्त है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एचआईवी जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जो 12 अक्तूबर, तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और दो महीने तक चलने वाले इंटिग्रेटिड हेल्थ चेकअप अभियान का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि “राज्य सरकार एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी केंद्रों में निःशुल्क उपचार करवाने वाले व्यक्तियों को एक हजार 5 सौ रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता और पीड़ितों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 3 सौ रुपए से लेकर 8 सौ रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही उपचार के लिए आने वाले व्यक्तियों को फ्री बस यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआईवी की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क की जाती है और जांच

करवाने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके अध्ययन के लिए सरकार ने आई.सी.एम.आर से सम्पर्क किया है। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और समाज निर्माण में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के लिए प्रदेश सरकार ने खेल नीति में बड़े बदलाव किए हैं ताकि युवा खेल के क्षेत्र में प्रदेश व देश का नाम रौशन कर सकें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री का आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा फिलहाल टल गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आपदा में प्रदेश को भरपूर मदद का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने आज राजभवन शिमला में राज्य के छह सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम निरंतर अपडेट किए जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहे। राज्यपाल ने कहा कि आज के तकनीकी युग में विश्वविद्यालयों के डिजिटलीकरण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने से अनुसंधान व नवाचारों का व्यवसायीकरण हो सकता है, जो संस्थानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में और अधिक योगदान देगा।

मुकेश अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने बाथू-बाथड़ी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। अग्निहोत्री ने कहा कि खड्ड का रास्ता किसी कारण बाधित होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जांच के लिए ऊना के उपायुक्त को निर्देश दिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ के कारण ऊना जिला में अलग-अलग हादसों में हुई 14 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि निराश्रित बच्चों व महिलाओं सहित समाज के संवेदनशील वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वे आज शिमला में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के तहत गठित राज्यस्तरीय समिति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार गठन के तुरंत बाद सौ करोड़ रुपये के सुख-आश्रय कोष व सुख-आश्रय योजना की शुरुआत की।

हर्षवर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, कारीगरों और बुनकरों को सूक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। वे आज शिमला में हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हर्षवर्धन चौहान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए बोर्ड की सराहना की।

जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुलिस कर्मियों को एच.आर.टी.सी बसों में मिल रही यात्रा सुविधा को वापिस लेने के प्रदेश सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों से बस की यात्रा करने के बदले सभी पुलिस कर्मी हर महीने अपने वेतन से सरकार द्वारा निर्धारित धन राशि कटवाते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो पुलिस बल हर साल एच.आर.टी.सी को 5 करोड़ रुपये का आर्थिक सहयोग कर रहा है उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुलिस बल की कार्य विविधताओं को देखते हुए अनुदानित यात्रा का प्रबंध किया गया था और सरकार को पुलिस कर्मियों के लिए इन सेवाओं को पुनः बहाल करना चाहिए।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को लेकर आज नगर निगम शिमला व शहरी विकास विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम के तहत कई क्षेत्रों में विद्युत के खम्बों पर केबल के जाल बनाए जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि इससे शहर की सुन्दरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही यह सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर विषय है। विक्रमादित्य सिंह ने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को इन केबल वायर को तुरंत हटाने और एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण व संतुलित विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। चंबा में आज जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही।

पठानिया ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ज़िले में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 86 करोड़ 54 लाख से अधिक की राशि खर्च की गई। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने चंबा ज़िला में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की।

मौसम

प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और विभिन्न स्थानों पर रूक-रूक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही वर्षा के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश में चार राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 3 सौ 38 सड़कें अवरूद्ध हैं। इसके अलावा 4 सौ 88 बिजली के ट्रांसफार्मर व एक सौ 16 पेयजल परियोजनाएं भी ठप्प हैं। किन्नौर जिला के निगुलसेरी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूस्खलन से बार-बार बाधित हो रहा है। मौसम विभाग ने 18 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में नंगल डैम क्षेत्र में सर्वाधिक एक सौ 15 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा कसौली में 87, ऊना में 86 व नैना देवी में 82 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा—एडस से पीड़ित रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत्त।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता व प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दिया बल।

- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से पुलिस कर्मियों की परिवहन निगम की बसों में यात्रा सुविधा फिर से बहाल करने की उठाई मांग।
- प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से जनजीवन प्रभावित— 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग व 3 सौ 38 सड़कें अवरुद्ध।